SHRI CHINTA MOHAN: About essential drugs, we are watching the situa-tion...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्र

*406. **श्री अजीत जोगी :**
श्री बी० के० हरिप्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अभी तक स्थापित किये गये औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में खंड स्तर पर औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) देश में आदिवासी क्षेत्रों में और अन्य अल्प विकसित जिलों में, जहां कोई उद्योग नहीं है, स्थापित किये गये औद्योगिक विकास केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना के अधीन मध्य प्रदेश को 6 विकास केंद्र आवंटित किए गए हैं, इन सभी केन्द्रों हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है और उसकी घोषणा भी कर दी गई है । इनमें से भिंड, धार, दुर्ग, गुना, रायपुर और रायसेन जिलों में से प्रत्येक जिले में एक एक केन्द्र है । इन क्षेत्रों में धार, दुर्ग तथा रायपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासियों का संकेन्द्रण है।

(ग) चुने गए तथा घोषित किए गये 63 विकास केन्द्रों में से 50 क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्र हैं।

पंजाब में उद्योगों को आर्थिक राज सहायता

*407. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पंजाब में उद्योगों को केन्द्र सरकार द्वारा कोई आर्थिक राज-सहायता नहीं दी गई है ; यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) उस राज्य के उद्योगों को अन्तिम बार राजसहायता किस वर्ष प्रदान की गई थी और उस राजसहायता की राशि कितनी थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 30 सितम्बर, 1988 से बन्द कर दी गयी थी । यह योजना राज्य सरकारों के जरिए चलायी गयी थी और केन्द्र सरकार ने राज्यों को केवल राजसहायता की राशि की प्रतपूर्ति की थी । इस योजना के चालू रहने के दौरान पंजाब सरकार द्वारा वितरित की गई राजसहायता की राशि के लिए वर्ष 1988–89 से 1990–91 के दौरान राज्य सरकार को 2.9 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी ।

Export of Coir products

*408. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that MRP and floor price for the export of Coir products, hamper free trade-, as contemplated in the new industrial policy; and

(b) if so, what steps Government propose to take to remove these controls in order to promote foreign trade.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का विस्तार

*409. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अगस्त, 1991 के **ट्रिब्यून** में "माइल्स टु गो इन फूड प्रोसेसिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार करने के लिए काफी संभावनाएं हैं ;

(ख) देश में हर वर्ष पैदा की जाने वाली फल और सब्जियों की अनुमानित मात्रा क्या है और मार्च, 1991 के अंत में देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता कितनी थी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग के अनुसंधान आरम्भ करने के लिए कोई प्रयास किये हैं, ताकि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किये जा सकें; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांग) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में फल और सब्जियों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्रमशः 26.08 मिलियन टन और 53.88 मिलियन टन था । चुनींदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अनुमानित क्षमता मार्च, 1991 में इस प्रकार थी :—

क्रम संख्या	उत्पाद	मात्रा/क्षमता
1.	फल एवं सब्जी उत्पाद	8.94 लाख मी० टन प्रतिवर्ष
2.	चावल	1400 लाख मी० टन धान प्रतिवर्ष
3.	गेहूं उत्पाद	130—140 लाख मी० टन गेहूं प्रतिवर्ष
4.	मांस और मांस उत्पाद	10.25 लाख मी० टन प्रतिवर्ष
5.	बीयर	1.30 लाख किलो लीटर प्रतिवर्ष
6.	फल रस पेयों सहित मृदु पेय	225 मिली० लीटर की 36000 लाख बोतलें प्रतिवर्ष
7.	प्रशीतक सहित मछली प्रसंस्करण	2935 मी० टन प्रतिदिन

मंत्रालय ने ऐसे अनुसंधान एवं विकास को सहायता एवं बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीमें भी तैयार की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है :—

(क) उचित पैकेजिंग के कच्चेमाल का विकास जिसमें कम लागत की और साफ-सुथरी पैकिंग पर जोर दिया गया गया है ।

(ख) कृषि जलवायु दशाओं के आधार पर प्रसंस्करण के लिए अच्छी फसल देनेवाली सब्जियों और फलों की किस्मों का पता लगाना ।

(ग) सोया पर आधारित उत्पादों का विकास ।

(घ) पारंपरिक खाद्य पदार्थों और आम खाद्यान्नों तथा डेरी उत्पादों पर आधारित नये खाद्य उत्पादों का विकास ।

(ङ) ऐसे उत्पादों को तैयार करने के लिए उपस्कर डिजाइनों का विकास ।